

संपादक की कलम से

भीषण गर्भी से खुला काम करने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों

भारत में हाल ही में आई भीषण गर्मी ने कई क्षेत्रों में तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा दिया है, जिससे डेली वर्कर्स, खासकर डिलीवरी कर्मियों और दिहाड़ीदार मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों में इजाफा हुआ है। इस प्रकार के खुला काम करने वाले इस दौरान श्रमिक पर्याप्त स्वास्थ्य-सुरक्षा उपायों और न्यूनतम ब्रेक के बिना चरम मौसम की स्थिति के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण गर्मी से थकावट और निर्जलीकरण से पीड़ित हुए हैं, जिससे पता नहीं कितनों की जान असमय गई है। दिहाड़ीदार मजदूर स्थायी नौकरियों के बजाय अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस काम करते हैं। इस में उबर, स्विगी और जोमैटो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अस्थायी, लचीले और प्रोजेक्ट-आधारित काम करने वाले भी शामिल हैं। ये नौकरियाँ लचीलापन प्रदान करती हैं, लेकिन इन लोगों को पारंपरिक रोजगार से जुड़े लाभों और सुरक्षाओं का अभाव होता है। अगर वे काम नहीं करेंगे, तो उनके घर खाना नहीं पकेगा। यह उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है। ऐसे लोग अक्सर काफी गरिबी में जीने के लिए विवश होते हैं। साफ पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित झागियों के घर टिन या तारपेलिन की छतों के नीचे

तपती गर्मी झेलते हैं। चूंकि ये काम ज्यादातर खुले वातावरण में ही करने पड़ते हैं, तो भीषण गर्मी में इन लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। ऐसे श्रमिकों को अक्सर स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ या सवेटन अवकाश की सुविधा नहीं मिलती, जिससे बीमारी या चोट के समय वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। श्रमिकों की आय अत्यधिक परिवर्तनशील और अप्रत्याशित होती है, जिससे वित्तीय योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। श्रमिकों को कठोर कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चरम मौसम का सामना करना भी शामिल है। इनको आमतौर पर स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में बगीकृत किया जाता है, जिससे उन्हें कई श्रम सुरक्षा से विचित रखा जाता है जो औपचारिक कर्मचारियों को प्राप्त होती है। ऐसे विपरीतसमय में श्रमिकों को संरक्षण और निष्पक्ष व्यवहार के लिए आवश्यक प्रबंध करने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करनाबहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए: राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 का उद्देश्य वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल कायम करेगा। वर्कर्स के लिए एक न्यूनतम वेतन नीति स्थापित करना ताकि एक स्थिर आय और न्यूनतम भुगतान किए गए घंटे या कमाई सुनिश्चित हो सके। जैसे सिंगापुर के प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों में श्रमिकों के लिए कार्य-चोट बीमा और पेंशन कवरेज का विस्तार करना शामिल है, जिसका भारत भी अनुकरण कर सकता है। वर्कर्स को कर्मचारी के रूप में मान्यता देना या उन्हें समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना समय की मांग है। इसमें संगठित होने और यूनियन बनाने का अधिकार शामिल है। उदाहरण के लिए: यूके और कैलिफोर्निया में कानूनी लड़ाइयों के कारण वर्कर्स को कर्मचारी के रूप में मान्यता मिली है, जो न्यूनतम वेतन और अन्य लाभों के हकदार हैं। सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए जिसमें सुरक्षात्मक गियर, नियमित ब्रेक और चरम मौसम से श्रमिकों को सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। उदाहरण के लिए: निष्पक्ष व्यवहार और शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं करेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहेगा। 2024 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से रोकने में दो राज्यों की सबसे बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े राज्य हैं। दोनों ही राज्य हिंदुत्व की प्रयोगशाला माने जाते हैं। दोनों राज्यों में लंबे समय से भाजपा सत्ता में है। इन राज्यों में भाजपा का अनेक छोटे-बड़े सहयोगी दलों के साथ गठबंधन भी है। महाराष्ट्र में भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार में है। जून 2022 में उद्धव ठाकरे की महा विकास अधारी की सरकार को गिराकर भाजपा ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जा कर लिया। ठीक इसी तरह भीजे अजित पवार ने दो तिहाई से ज्यादा विधायक तोड़कर चाचा शरद पवार की एनसीपी पर कब्जा कर लिया। जाहिर तौर पर यह तोड़फोड़ केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हुई थी। महाराष्ट्र में

को बढ़ावा दन के लिए भारत में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, लोकन इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र श्रम न्यायालयों की स्थापना करना और यह सुनिश्चित करना कि उनमें मामलों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से निपटाने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए: कतर की श्रम विवाद समितियों ने न्याय तक पहुँच में सुधार किया है, लेकिन देरी और प्रवर्तन संबंधी मुद्दे बने हुए हैं, जिसके लिए और सुधार की आवश्यकता है। वर्कर्स की रोजगार क्षमता और आय क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करनाभी आवश्यक है। इसमें वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण शामिल हो। उदाहरण के लिए: स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों का विस्तार करके वर्कर्स को विशेष रूप से लक्षित किया जा सकता है, ताकि उन्हें प्रासंगिक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण और पहुँच को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सेवा वितरण में सुधार के लिए वर्कर डेटा को राष्ट्रीय श्रम डेटाबेस में एकीकृत करना श्रमिकों के लिए फायदेमंद स्कीम बनाने में सहायक होगा। उदाहरण के लिए: भारत का ई-श्रम पोर्टल, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, वर्कर्स को शामिल करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें समय पर लाभ मिले।

ਛਵਾ ਮੈਂ ਘੁਲਤੇ ਜਹਰ ਕੀ ਬੇਣਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਖੀਰ

हवा में घुलते जहर यानी वायु प्रदूषण का खतरा ऐसा है जो दिखता भी है और महसूस भी होता है। लेकिन इस खतरे का मुकाबला करने के लिए जब काम करने की बारी आती है तो सब एक-दूसरे का मुंह ताकते नजर आते हैं। यूनिसेफ और हैल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट् (अमेरिका का एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी शोध संस्थान) की रिपोर्ट व्हास्टेट ऑफ ग्लोबल एयरडॉ की ताजा रिपोर्ट बढ़ते वायु प्रदूषण के इन्हीं खतरों की ओर आगाह करती है जिनको लेकर हम बेपरवाह नजर आते हैं।

इस रिपोर्ट में यह चौकाने वाला तथ्य सामने आया है कि अकेले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में हुई मौतों का एक चौथाई भारत से जुड़ा है। हैरत की बात यह है कि मौतों के ये आंकड़े वर्ष २०११ के उस दौर के हैं जब कोरोना महामारी के चलते आम तौर पर सभी तरह का यातायात काफी समय तक बाधित रहा। दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण ८४ लाख मौतें हुईं जिनमें से २१ लाख भारत में हुई हैं। साफ है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह साल दर साल लाखों लोगों की जान की दश्मन बन गई है।

कहना न होगा पर सच यह भी है कि दुनिया भर में युद्ध, आतंकवाद व गंभीर बीमारियों से मौतों का जितना खतरा है उससे कई गुना ज्यादा खतरा हवा में घुलते इस जहर का है। खास तौर से जब हम भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के कारणों की पढ़ताल करते हैं तो कुप्रॄष्ण के बाद इसकी बड़ी बजह वायु प्रदूषण ही है। वर्ष २०२१ के दौरान भारत में १,६९,४०० बच्चों की मौत वायु प्रदूषण जिनत कारणों से हुई, जबकि दुनिया भर में वायु प्रदूषण के संपर्क में अनें से पांच वर्ष से कम उम्र के ७००,००० से अधिक बच्चों की मौत हुईं। इसी अवधि के दौरान शहरों में वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भले ही मोटर-वाहन हों पर एक तथ्य यह भी है कि इस प्रदूषण से बीमारियों का शिकार निचले तबके से जुड़े लोग ज्यादा होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे परी दुनिया में सिर्फ १० प्रतिशत लोग ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी ग्रीनहाउस गैसों के अधिकांश रक्तरुर्जन के लिए जिम्मेदार हैं त्वेक्षित उमसका नक्शान समझी दिया जाए

उत्सवों का हाई जिन्मन्डर हर लापकन उत्सवों मुख्यतया लग्नों तथा बुलावां, भात तौर पर निर्धन वर्ग को उठाना पड़ता है। वायु प्रदूषण को लेकर पिछले दिनों ही आई एक अन्य रिपोर्ट में चेताया गया था कि जहरीली हवा का यही हाल रहा तो भारतीयों की औसत उम्र छह साल कम होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इस जहर का असर कम करने के लिए सख्त कानून-कायदे बनाकर सजा और जुमारें तक के प्रावधान भी खबर हुए हैं, लेकिन असली जरूरत जन-जागरूकता की है।

(कन्फ़रेन्स का शब्द) नमस्ते जिसका अध्य ना पूछकर हाता है, आंदोलन चला। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर हस्तक्षेप करनी की सोची। इसी समय सुन्दरलाल बहुगुणा जी कर्नाटक आए और उन्होंने चिपको आंदोलन का अनुभव ग्रामीणों को बताया और कहा कि आप भी इस काम को आगे बढ़ाएं। उनसे प्रेरणा लेकर सालकर्नी गांव से विरोध शुरू हुआ और आसपास के गांवों में फैला। यहां पदयात्रा की, जिनमें महिलाएं व युवा शामिल थे। इस आंदोलन का विस्तार जल्द ही पड़ोसी गांव सिद्धापुर तालुका

उप्र और महाराष्ट्र ने रोका भाजपा का दूध



महायुति सरकार बनाने के पीछे असली मकसद लोकसभा चुनाव था। लेकिन महाराष्ट्र की 48 सीटों में से केवल 17 पर महायुति गठबंधन जीत सका। इसमें 9 पर भाजपा, 7 पर शिवसेना और 1 पर एनसीपी ने जीत हासिल की। इसके बावजूद उद्घव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर 30 सीटों पर जीत हासिल की। आश्वर्यजनक रूप से कांग्रेस को सर्वाधिक 13, शिवसेना (यूटीटी) को 9 और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को 8 सीटें मिलीं। केंद्रीय एजेंसियों के दुसरोंयोग के जरिए पार्टियों को तोड़कर और तमाम सामाजिक समीकरण साधकर भी महाराष्ट्र में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भाजपा की जीत में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका थी। यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें जीतकर भाजपा ने पूरे देश में 282 सीटें हासिल की थीं। इसके बाद 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के सामने भी भाजपा ने 62 सीटें जीतकर 303 सीटों का बड़ा बहुमत हासिल किया। 2024 के चुनाव में सपा

जाग्रेस गठबंधन के सामने भाजपा केवल 33 सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार कई मायने में गौरतलब है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश भाजपा के हिंदुत्व का केंद्र बना। भाजपा के उभार में राम मंदिर आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। बाबरी मस्जिद तोड़कर (6 दिसम्बर, 1992) भाजपा और संघ ने जिस राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था, वह इस साल बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को हुए उद्घाटन के समय पूरे देश को भगवा झंडों से पाठ दिया गया। गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ की छवि उग्र हिंदुत्वादी नेता की है। योगी में कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया। गुंडे खत्म करने के नाम पर सैकड़ों लोटे-मोटे अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया। इनमें भी ज्यादातर मुस्लिम थे। इद, मुहर्रम और बकरीद पर मुसलमानों को सख्त हिदयतें दी जाती हैं, जबकि विनौजवान हिंदुओं को चटाकर मस्जिदें बैंद बजाने और समुदाय अपमानित करने वाले मिलता है। इनमें अब और दलित नौजवानों की किया जाता है। लेकिन नौजवान नौकरी समुचित आरक्षण तो मांग करते हैं तो मिलती हैं। इस व्यापकी मीडिया की भाषा में जाता है। उत्तर प्रदेश आंदोलन की ही मान्यवर कांशीराम आंदोलन की भी संप्रदायिक उग्रता। विभाजन के बावजूद नितांत हिंदुत्व के नहीं जीत सकी। भविष्यत पिछड़ा कार्ड खेलने दलित और गैर यात्रों और यादवों नफरत पैदा करके जनाधार बनाने में इसके बावजूद उसके पर अनेक छोटे-

गठबंधन किया। इस चुनाव में भी मोदी और योगी को अपशब्द कहने वाले ओमप्रकाश राजभर से भाजपा ने गठबंधन किया। राम का अपमान करने वाले संजय निषाद को साथ लिया। कांशीराम के साथी रहे सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ भी भाजपा ने गठबंधन किया। इतने प्रयोग और आक्रामक प्रचार के बावजूद भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। सामाजिक समीकरण, कट्टर हिंदुत्व और पानी की तरह पैसा बहान के बावजूद भाजपा को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्यों पराजय मिली? दरअसल, विपक्षी ईंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार में संविधान और लोकतंत्र बचाने का मुद्दा जोर-जोर से उठाया। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान प्रतिनिधित्व और सम्पान देने का वादा किया। नतीजे जाहिर करते हैं कि विपक्ष के इस एजेंडे का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। इन दो राज्यों ने भाजपा और मोदी के मसूबों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े सूबे हैं। करीब एक चौथाई सीटें इन राज्यों से आती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 और महाराष्ट्र की 48 यानी कुल मिलाकर 128 सीटों में से भाजपा केवल 50 सीटें जीत सकी। इन प्रदेशों में भाजपा 40 फीसदी सीटें भी जीतने में कामयाब नहीं हुई। नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से रोकने में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी भूमिका है। 18वीं लोकसभा का यह चुनाव क्यों बेहद खास रहा? आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बेताब नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पिछले दो साल से बार-

बार संविधान बदलने की बात की जा रही थी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाकर नया संविधान लागू करने के लिए देश में माहौल तैयार किया जा रहा था। विदित है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के मूलभूत ढाँचे को नहीं बदला जा सकता। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ़ ने संसद में मूलभूत ढाँचे की वैधता पर पुनर्विचार करने की बात उठाई। जाहिर तौर पर यह सब मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा था। इसी दरमियान 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष विवेक देवराय ने बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक बताते हुए नया संविधान लिखने की वकालत की। यह सिलसिला चुनावी ऐलान के बाद और आगे बढ़ा। अनंत कुमार हेंगड़े से लेकर ज्योति मिथ्या, लल्लू सिंह, अरुण गोविल और गिरिराज सिंह जैसे बड़बोले भाजपा नेताओं ने संविधान बदलने के लिए 400 सीटें जीने का दावा किया। यह मुद्दा चुनाव में इतना भारी पड़ जाएगा खुद मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा। गौरतलब है कि संविधान बदलने की बात करतई हवा में नहीं थी। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में संघ के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी अपनी पितृ संस्था की हसरत को पूरा करने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन दो बड़े राज्यों ने उनके मनसूबों पर पानी ही नहीं फेर दिया बल्कि उनकी हैसियत भी बता दी।

चिपको की तरह दक्षिण भारत का अप्पिको

आदोलन का असर हुआ कि कनाटक का पश्चिम घट में हर पड़ा का ने पर सरकार ने रोक लगाई, जो अब भी जारी है। यह अहिंसक विद्यार्थी तरीके का आंदोलन था। पेड़ों से लोग चिपक गए थे। यह कानून की ही नवी था, वास्तव में वर्तों का कठान रोकने के लिए वर्तों से चिपक गए। बिलकुल उत्तराखण्ड के चिपको आंदोलन की तरह। चिपको दोलन की 50 वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है। इस आंदोलन ने हिमालय में कटाई पर रोक लगावाने में सफलता पाई थी। इसका देश-दुनिया में काफी प्रभाव हुआ था। कई जगहों पर इससे प्रभावित होकर लोगों ने पेड़, पहाड़, झील, पथर और खेतों को बचाने के लिए पहल शुरू की थी। इसके साथ, बंदी आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और पर्यावरण जागरूकता के युहिम होड़ी। आज मैं इस कॉलम में चिपको से प्रेरणा लेकर कनाटक घटने वाली एक महत्वपूर्ण पहल अपिको के बारे में करना चाहूँगा। हाल में मुझे चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर अपिको आंदोलन के सूत्रधार बनाने वाले से चिपको का मौका पिला। तीनोंपाट के मन्त्रियों ने तो

बैठक में हिस्सा लेने आई थे। इस दौरान उन्होंने मुझे अपिको आंदोलन प्रेरणादायक कहानी सुनायी। वे देश-दुनिया में पर्यावरण के प्रति चेतना नाम की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चिपको आंदोलन के बारे नाम तचित हांगा। मुझे एक-दो बार चिपको के प्रणाली सुन्दरताल बहुगुणा भी देखने वाले बनने का मौका मिला है। मुझे उनकी एक बात याद है, जो उन्होंने इन्डॉर की एक बैठक में कही थी। उन्होंने कहा था कि पेड़ भी जिंदा और वे बातें भी करते हैं। अगर उन्हें गले से लगाते हैं तो सुकून मिलता चिपको आंदोलन महिलाओं की अगुआई में हुआ था। इसका श्रेय गुणा जी भी महिलाओं को देते थे। वे कहते थे महिलाएं जंगल का महत्व छोड़ से जानती हैं, क्योंकि वह उनका मायका है, जो हर संकट के समय के साथ रहता है। जंगल से ही उनकी सब जरूरतें पूरी होती हैं। फल, गां, शहद, इंधन, चारा, पानी, रेशे सब कुछ। इस आंदोलन ने वन कटाई केवल रोक लगाने में सफलता पाई थी, पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने बचाया था। बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति चेतना जागाई थी। रंग हेंगड़े दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में गोल्ड मेडलिस्ट अपनी पढ़ाई के दौरान ही हिमालय के चिपको आंदोलन में शामिल हो थे और कई गांवों में घमे थे और कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। वे शुरूआत व्याधाव से घुमककड़ हैं, और पर्यावरण के प्रति उनका विशेष लगाव रहा लेकिन सुन्दरताल बहुगुणा और चिपको की प्रेरणा से उनकी जीवनधारा बदल गई। उन्हें बड़ी नाकरियों के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने उनकी

भूमि कनाटक का हो बनाया, जहा के व रहन वाल ह। रंग हेगडे जब पढ़ाई के बाद उनके गांव वापस लौटे तब तक घने जंगल पड़ में बदल रहे थे। हरे पेड़ कट रहे हैं। इससे पांडुरंग व्यथित हो गए, उनका बचपन याद आ गया। बचपन में वे खुद घर के मवेशी जंगल में तैरे थे, तब बहुत घना जंगल देखा था। हरे पेड़, शेर, हिरण, जंगली पर, जंगली भैंसा, बहुत से पक्षी और तरह-तरह की चिंडियाएं देखी थीं। कुछ सालों के अंतराल में इसमें कमी आई। अस्सी के दशक की बात है। लाल वाल की तरह पश्चिमी घाट में वनों की कटाई होने लगी। यह उष्ण अंबंधीय वन जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जंगलों पर लोगों की जीविका व जीवन निर्भर था। लेकिन सरकार की बननीति के चलते यहां जैव विविधता व पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा। इससे न केवल यहां लोगों का जीवन कठिन हुआ बल्कि यहां के पीने के पानी और खेती की वाई का भी संकट बढ़ने लगा। चिपको से प्रेरणा लेकर यहां भी अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द) नाम से जिसका अर्थ भी चिपको ही होता है, दोलन चला। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर हस्तक्षेप करनी की सोची। समय सुन्दरलाल बहुणा जी कर्नाटक आए और उन्होंने चिपको दोलन का अनुभव ग्रामीणों को बताया और कहा कि आप भी इस काम आगे बढ़ाएं। उनसे प्रेरणा लेकर सालकनी गांव से विरोध शुरू हुआ और सपास के गांवों में फैला। यहां पदयात्रा की, जिनमें महिलाएं व युवा मेल थे। इस आंदोलन का विस्तार जल्द ही पड़ोसी गांव सिंधुपुर तालुका

मोदी पर आरएसएस का छुपा वार

- जगदीश रत्ननाना
कई ऐसे लोग हैं जो इसमें आरएसएस दोमुंहापन देखते हैं और जो मानते हैं कि सभा भाजपा का वैचारिक अभिभावक है एवं उन सभी ज्यादतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहते हैं जो हमने मोदी-युग के दौरान देखी थीं आखिरकार मोदी आरएसएस की विचारधारा विद्यार्थी हैं और वे वही ढोल बजा रहे हैं जो संगठन ने उन्हें सिखाया है। बाकी सब जो रहा है वह आरएसएस की छत्रछाया में नकुशती है और नियंत्रण का अस्थायी बदलाव इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि 2024 के चुनावों पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का भाषण संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करता था कहा जाता है कि भागवत ने उनकी नियंत्रण किए या उनका नाम लिए बिना सब कुछ विद्यार्थी हैं और अपने इच्छित लक्ष्य के बारे में कहा संदेह नहीं छोड़ा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि चुनाव युद्ध नहीं है, दोनों पक्षों को सुना के लिए एक दृष्टिकोण है और सच यह है कि सेवक वह है जो मर्यादा में रहकर और अहंकार के बिना सेवा करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि मणिपुर में मुद्दों को एक साल से अधिक समय से उपेक्षित किया गया है। समझदारी का इशारा देने वाले इन शब्दों को और किसकी अनिर्देशित किया जा सकता है? भागवत के बयान के बाद इसे व्यापक रूप से मोदी विरोधी वक्तव्य के रूप में देखे जाने के बाद अज्ञात स्रोतों द्वारा यह संघ ने यह स्पष्ट करना उचित समझा है कि वह उस व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई झरना नहीं रखता है जिसने अभी तीसरी बार अधिकारी तेरा दोस्तों बारी तीसरी बारी है।

क्षेत्र में सीट खोना भी शामिल है। यह देखते हुए कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के हाथों में सिमट गई है और अपने दम पर सोच नहीं सकती है तो इन हालातों में यह चुनाव आरएसएस में कछ वास्तविक पुनर्विचार के लिए ट्रिगर हो सकते हैं। आज यह आरएसएस की उस दुविधा को सामने ला रहा है कि इसके एजेंडा का नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया है, संघ एक ऐसी सरकार से शक्ति और संसाधन प्राप्त कर सकता है जो अब एक दशक से अधिक समय से पूर्ण नियंत्रण में है लेकिन ऐसा लगता है कि यह उस तौर तरीके को नापसंद कर रहा है जिसे इस प्रक्रिया में मोदी ने अपने चारों ओर बनाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो आरएसएस के नजरिए से नीतियां 'अच्छी' हैं लेकिन उन्हें व्यवहार में लाने देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना, अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध, नागरिक संशोधन अधिनियम (सीए) का एजेंडा, समान नागरिक संहिता की ओर कदम, ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध आदि शामिल है या ये उस सड़ी हुई संस्कृति के 'उपहार' हैं जो एक ऐसी पार्टी में अंतर्निहित हो गई है जिसने हमें चुनावी बांडों में देखा गया भ्रात्याचार, लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा, भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में घिरावट, गैर-भाजपा सरकारों को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और यह सब कुछ अगर बढ़ती संपत्ति और आय असमानता को लेकर है जो राष्ट्र की गर्म बहस बनने और बने रहने का बादा करता है? यह आरएसएस को खुश करने के लिए साध्य है लेकिन इस साध्य के साधनों के बारे में क्या कहा जाए?

वाला व्याक सहा नहा ह। सघ के द्वितीय सरसंचालक आरएसएस गोलबलकर ने एक बार कहा था कि- आरएसएस कार्यकर्ता की 'असाधारणता' ठीक ऐसी होनी चाहिए कि हर कार्यकर्ता खुद को 'साधारण' माने। आज आरएसएस को भाजपा के एक ऐसे प्रधानमंत्री से जूझना होगा जो खुद को इश्वर का भेजा हुआ और गैर-जैविक अवतार बताते हुए स्वयं को प्रधान सेवक कहता है और जो यह कहते नहीं थकता कि वह कितना असाधारण है। आरएसएस के नजरिए से यह सरल सवाल है कि क्या आपके काम करने के भुगतान की यह बहुत अधिक कीमत है या क्या ऐसा नहीं है? क्या यह आरएसएस की वर्षों पुरानी इच्छाओं के सच होने का स्वर्णम काल है जिसमें अयोध्या आखरकर अपन स्वयंसवका के बाच चारत्र निर्माण करना संघ का घोषित लक्ष्य है। यह लक्ष्य धनबल, ग्लैमर मार्केटिंग और धृणा की भाषा के युग में कैसे साध्य है जिसमें चुनाव अभियान में जहर घोलने के लिए प्रधानमंत्री मटन, मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं?

गांधी ने हमें बताया कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में वे केवल साधनों के बारे में चिंतित थे, उसके अंत के बारे में नहीं। वे कहते हैं कि, 'साधन सभी चीजों से ऊपर हैं। मैं कहूँगा कि साधन सब कुछ के बाद हैं। साधन जैसा है, अंत वैसा ही होगा। मुझे लगता है कि लक्ष्य की दिशा में हमारी प्रगति हमारे साधनों की शुद्धता के सटीक

